

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 55/18

GCMS NO 2018/00257

दुर्गालाल पुत्र श्योबक्श जाति पूर्विया निवासी कैमला तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रमेश चंद पुत्र दुर्गालाल

2. रामचरण पुत्र दुर्गालाल जातियान पूर्वियां निवासीयान कैमला तहसील नादौती जिला करौली

3. तहसीलदार नादौती लैण्ड होल्डर

रेस्पो0

अपील विरुद्ध मु0नं0 358/88 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.89 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री पी0एल0गोयल


अभिभाषक रेस्पो0 श्री बनवारी लाल

दिनांक 18.07.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.89 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/वादीगण द्वारा एक वाद घोषणा खातेदारी व भूमि विभाजन इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 सगे भाई हैं तथा प्रतिवादी न0 1 वादी न0 1 व प्रतिवादी न0 2 का पिता है। प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे भूमि ख0न0 78,129,150 व 151 वाके ग्राम कैमला मे स्थित है। जो प्रतिवादी न0 1 की पैतृक सम्पति है। इस भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण का हिन्दु विधि के अनुसार बराबर का हिस्सा है। वादी का उक्त आराजीयात मे 1/3 हिस्सा है। वादी का उक्त आराजीयात मे 1/3 हिस्सा होता है। अब तक वादी एवं प्रतिवादीगण शामिल रहकर उपरोक्त भूमि से लाभान्वित होते चले आ रहे हैं परन्तु अब प्रतिवादीगण न0 1 व 2 ने साजकर वादी को अलग कर दिया है व उसको 1/3 हिस्सा की भूमि भी नहीं दी है। वादी के पास कृषि के अलावा अन्य कोई आजिविका का साधन नहीं है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से बंटवारा कराने की कहने पर प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। इस प्रकार वादी अपने हक मे विवादित आराजीयात का 1/3 भाग की घोषणा खातेदारी की करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी द्वारा चाही गई। दौराने दावा वकील प्रतिवादी द्वारा दिनांक 30.8.89 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर्डर 9 नियम 7 जा0दी0पेश कर एक तरफा कार्यवाही दिनांक 4.4.89 को हटाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि ख0न0 78,129,150 व 151 जो कि अपीलांट की खातेदारी प्रारंभ से रही है, उसके पैतृक सम्पत्ति होने के संबंध में वादी/रेस्पो0 न0 1 द्वारा कोई जमाबंदी पेश नहीं की, मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त स्थिति के उपरान्त भी भूमि को पैतृक मानकर वादी/रेस्पो0 न0 1 का दावा खिलाफ कानून डिक्री किया है। विवादित भूमि के पैतृक होने बावत कोई दस्तावेजी सबूत अर्थात् अपीलांट की खातेदारी से पूर्व अपीलांटके पिता की खातेदारी होने के संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं होने के उपरान्त भी महज वादी/रेस्पो0 न0 1 के अभिवचन पर विश्वास कर दावा वादी डिक्री किया है। अपीलांट अनपढ व अंगूठा वाला व्यक्ति है जिसका बेजा फायदा उठाकर रेस्पो0 1 व 2 द्वारा खिलाफ कानून अपीलांट से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके अनपढ होने का फायदा उठाकर जबाब दावे में इकवाल कराया, जिसकी कानूनन कोई अहमियत नहीं है क्योंकि विवादित भूमि कभी भी अपीलांट की पैतृक भूमि नहीं रही और ना ही अपीलांट को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई और ना ही विवादित सम्पत्ति के पैतृक होने का कोई रिकार्ड पत्रावली पर पेश हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को अनदेखा कर दावा डिक्री किया है। जो निरस्त योग्य है। सम्पूर्ण दावा हाजा में वादी/रेस्पो0 1 ने यह कही नहीं बताया है कि विवादित सम्पत्ति किस प्रकार से पैतृक है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने महज वादी के वेग अभिवचन पर विश्वास कर खिलाफ कानून निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। दावा हाजा में घोषणा के लिए कोई विनायदावा वादी/रेस्पो0 न0 1 द्वारा दर्ज नहीं किया है केवल बंटवारे का विनायदावा दर्ज है। ऐसी सूरत में घोषणा की दादरसी हेतु दावा हाजा में विनाय दावा के अभाव में दावा कानूनन पोषणीय नहीं था, मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजर अंदाज किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने दावा हाजा में दिनांक 27.12.89 को अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 व रेस्पो0/प्रतिवादी न0 2 की एक तरफा कार्यवाही मसूख कर प्रकरण में मुताबिक कानून बिना साक्ष्य लिए ही निर्णय पारित किया है। रेस्पो0 न0 1 ने दावा हाजा में अपनी खास बहिनें अर्थात् अपीलांट की तीनो पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए दावा हाज कानूनन नोन जोइन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज के नुक्स के आधार पर पोषणीय नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दू को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट के अत्यधिक बुजुर्ग होने तथा शारीरिक रूप से कोई कार्य /काश्त नहीं करने में असक्षम होने पर अपने बुढ़ापे की देखभाल हेतु पैसों की आवश्यकता होने पर व उसके दोनों लडकों द्वारा उसकी देखभाल नहीं करने पर उसने अपनी भूमि के विक्रय हेतु जमाबंदी की नकल पटवारी से दिनांक 16.2.18 को लेने पर भूमि की खातेदारी की पूछने पर उक्त भूमि उसके लडके रेस्पो0 1 व 2 के नाम होने की जानकारी हुई। जिस पर कानूनी सलाह व जानकारी करने पर दावा को रेस्पो0 न0 1 द्वारा गलत रूप से डिक्री कराने की जानकारी का पता चला। इस प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर


इल्म की अवधि में अपील अन्दर मियाद पेश की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजीयात की खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज फरमाई जावे।



रेस्पो० के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्पो० संख्या 1 की खातेदारी में भूमि ख०न० 78,129,150 व 151 वाके ग्राम कैमला में स्थित है। जो रेस्पो० न० 1 की पैतृक सम्पत्ति है। इस भूमि का रेस्पो० के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से कोई संबंध वास्ता नहीं है। रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत दावे में गांव वालों के समक्ष पक्षकारान के मध्य आपसी समझौता होने पर समझौते के अनुसार मौके पर बंटवारा किया जा चुका था। जिसके अनुसार ख०न० 78 रकबा 2.44 व ख०न० 151 रकबा 1.35 है० वादी के हक में आया था तथा ख०न० 129 रकबा 3.71 है० प्रतिवादी न० 2 रामचरण के हक में एवं ख०न० 150 रकबा 4.82 है० प्रतिवादी न० 2 अपीलांट दुर्गा के हक में आया था। इस प्रकार कागजात सरकार में उभयपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी समझौते के अनुसार वादी का वाद पत्र विधि अनुसार डिक्री किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध लगभग 28 वर्ष पश्चात पेश की गई है। जो प्रारंभतः मियाद बिन्दु पर खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आपसी समझौते से दावा डिक्री होने के विरुद्ध पेश की गई जो कानून चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात भूमि ख०न० 78,129,150 व 151 वाके ग्राम कैमला में स्थित है। जिसे वादी द्वारा अपने वाद पत्र में पैतृक सम्पत्ति माना है। प्रस्तुत दावे में भी विवादित भूमि के अपीलांट व रेस्पो० को 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का बंटवारा चाहा गया था। उभयपक्ष द्वारा गांव वालों के समझाने पर अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर भूमि ख०न० 78 रकबा 2.44 व ख०न० 151 रकबा 1.35 है० वादी रमेश चंद पुत्र दुर्गालाल के हक में तथा ख०न० 129 रकबा 3.71 है० प्रतिवादी न० 2 रामचरण के हक में एवं ख०न० 150 रकबा 4.82 है० प्रतिवादी न० 2 अपीलांट दुर्गा के हक में डिक्री किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये थे। उभयपक्ष आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं। अपीलांट का कथन रहा कि विवादित आराजीयात को रेस्पो/वादी द्वारा अपीलांट को गुमराह कर अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाकर गलत रूप से अगूठा निशानी करवाकर वाद पत्र को डिक्री कराया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो बंटवारा आपसी सहमति से किया गया है उसमें भूमि का वर्गीकरण बराबर बराबर नहीं किया गया है ना किसी प्रकार की साक्ष्य सबूत वाद पत्र में ली गई है। इस प्रकार अपीलांट की अपील अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलांट की अपील रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु०न० 358/88 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.89


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विवादित भूमि वादी की पैतृक होने के संबंध में विस्तृत जाँच करने के उपरान्त पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.8.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।



निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय
सवाई माधोपुर